Demand to grant relief package to people displaced by floods in Kosi river

श्री राजीव प्रताप रूडी (बिहार) : महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, सदन के समक्ष रख रहा हूं। महोदय, आपको याद होगा कि नेपाल में कोसी बांध टूटने के कारण बिहार में बड़ी मात्रा में क्षति हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की मृत्यु हुई थी तथा हजारों-करोड़ों का नुकसान हुआ था तथा बिहार में 20 जिले पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। प्रधान मंत्री जी ने उस समय आश्वस्त किया था तथा बिहार की इस त्रासदी के ऊपर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्होंने कहा था केन्द्र सरकार एक हजार करोड़ रुपया देगी। ऐसा पता चला है कि यह रिलीज करने की भी बात हुई थी तथा बिहार सरकार को देने की भी बात हुई थी। चुनाव के पहले इस प्रकार के आश्वासन दिए गए और मुझे यह भी पता चला कि उड़ीसा सरकार को भी साइक्लोन के लिए पैसा भेजा गया था। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद तुरन्त ही केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पत्र भेज करके कहा कि आपने पैसे इस्तेमाल नहीं किए हैं और आप पैसे तुरन्त वापिस कर दें। हाल फिलहाल हम लोगों ने देखा कि बजट में भी जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल को दिया गया, वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल उससे प्रभावित हुआ था। साथ-साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि गोरखा लैंड - दार्जिलिंग में जहां लगभग 32 लोग मारे गए थे, वहां भी इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। हम खुश हैं कि कम से कम सरकार चुनाव के दृष्टिकोण से चुनाव से पहले पैसे भेजती है, क्योंकि कुछ सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहती है और एक बार मतलब निकल गया कि हम पहचानते नहीं, का रुख सरकार अपनाती है। उसके बाद जैसे ही चुनाव सम्पन्न हो जाता है, तो केन्द्र सरकार यहां से पत्र भेजती है कि आप हमें पैसा वापिस दे दें, क्योंकि आपने पैसा खर्च नहीं किया या जो भी आधार बनाकर कहते हैं, यह घोर चिंता की बात है। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि सरकार ने तय किया था कि पड़ोस के देश में जिस प्रकार से तमिल बहुसंख्यक लोगों के ऊपर हादसा हुआ, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने पैसा दिया। लेकिन इस देश के भीतर जिस प्रकार से केन्द्र की सरकार लगातार उपेक्षापूर्ण रवैया उन राज्यों के प्रति अपना रही है जिनमें उनका शासन नहीं है, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, मैं समझता हूं कि सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए और जो परिस्थिति आज दिख रही है, उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार पक्षपाती रवैया अपना रही है। This is my appeal to the House and to the Government as well. As you know, after the division of the State, the situation in Bihar was critical. The economic situation was not very good.

The JD(U)-BJP ruled Government is there in Bihar. The Chief Minister had asked for Rs.1,400 crore. The Government agreed. The Prime Minister expressed his concern over the catastrophic situation which deserves attention. But, unfortunately, the situation which the Government is reflecting now is a very casual one. This is our request to the hon. Prime Minister and the Ministers concerned. Bihar is a very important State. It is a State which, after its division, lost the resources, mineral resources. We have just left with plains. Floods in the Kosi had a devastating effect there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

Violence and Obscenity in Media

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है और इससे लोगों को

बहुत दिक्कत भी हो रही है, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है और इससे लोगों को बहुत दिक्कत भी हो रही है। टेलीविजन चैनलस में, समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में जिस तरह से nudity, violence, obscenity and vulgarity का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, यह गंभीर चिंता का विषय है। हम लोग टेलीविजन चैनल्स पर समाचारों को भी पूरे परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर देख, सुन नहीं सकते हैं, ऐसी हालत हो गई है। अन्य प्रोग्राम्स की बात तो छोड़ दीजिए, जो समाचार आते हैं, उनके बीच में जो advertisements आते हैं, वे बहुत objectionable हैं जो कि हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ हैं।

महोदय, इससे पहले भी कई बार इस बात की मांग की जा चुकी है और इस सदन ने भी बहुत पहले एकमत से सरकार से कहा कि इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन nudity, violence, obscenity and vulgarity लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लग रही है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस मामले में सीरियस हो और इस पर पाबंदी लगाए। एक राज्य सरकार ने कानून बना कर के होटलों के काम करने वाली बार बालाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनको पकड़ने के लिए पूरी मुम्बई की पुलिस लगी रहती है। उन बार बालाओं से सौ गुणा ज्यादा यह गलत तरह के एक्सपोज़र्स टेलीविज़न चैनल्स में, मैगजीन्स में और समाचार-पत्र, पत्रिकाओं में आते हैं। सर, इन पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। इन पर सख्ती करने की जरूरत है। सोसायटी के लिए कोई मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप गवर्नमेंट को निर्देश दें कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे। धन्यवाद।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The whole House associates.

Liquor tragedy in Gujarat

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Thank you very much, Mr. Deputy Chairman, Sir. I am extremely sorry to quote a sad event which took place in the city of Ahmedabad in Gujarat and that too, in a working class area where poor people are living. Nearly 50 people are dead and many more are under treatment in the Government hospital because of the consumption of illicit liquor. The event took place 4-5 days ago. They were all very poor. Some of them were married. Their families are facing grave situation without any help from any corner. I have the details from the print media, electronic media and the leaders of my party that illicit liquor business in the city of Ahmedabad and all major cities of Gujarat is going on in connivance with the Police Department. Not only that it is going on in connivance with the Police, but also the State Administration. Certain illicit liquor is supplied by the mudda maal of the Court because whenever these illicit liquor shops are raided by the police and if they want to file a case in the court, they will have to seize the peeps etc. which are full of illicit liquor. They are kept for days together. But, when the case comes up after 5-6 months, they don't produce this before the court. In fact, that illicit liquor is sold through illegal channels of people who are associated with this illegal business. In spite of the matter being raised in the State